भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3759

11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

फास्ट-चार्जिंग अवसंरचना

3759. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जून, 2026 की तिथि के अनुसार, पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत कुल कितनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है और कितने प्रतिपूर्ति दावों का निपटान किया गया;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने से प्राप्त दैनिक ईंधन बचत और संबद्ध कार्बन डाइऑक्साइड में कमी संबंधी आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या जून, 2026 तक प्रमुख शहरी केंद्रों और प्रमुख राजमार्ग गलियारों में सार्वजनिक फास्ट-चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना संबंधी गति में तेजी आई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत, पात्र इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रेताओं को क्रय मूल्य में अग्रिम कमी के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसकी बाद में भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत ईवी की बिक्री तथा जिन ईवी के संबंध में दावे संसाधित किए गए उनकी संख्या और ओईएम को जारी की गई प्रतिपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत बिक्री की गई/समर्थित ईवी	**पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत जिन ईवी के दावे संसाधित किए गए उनकी संख्या**
25,33,638	24,19,266

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) एवं (घ): भारी उद्योग मंत्रालय की फेम-II स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, प्रमुख शहरी केंद्रों और प्रमुख राजमार्ग गलियारों सहित देशभर में 9,583 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित किए गए हैं। इनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा स्थापित 9,353 ईवीपीसीएस शामिल हैं, जो सभी फास्ट-चार्जिंग अवसंरचना हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत प्रमुख शहरी केंद्रों और प्रमुख राजमार्ग गलियारों सहित देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक फास्ट-चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, 9 राज्यों, नामतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली तथा 3 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी), अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 6,562 ईवी चार्जरों की स्थापना हेतु 689 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

*****